



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1251]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2011/आषाढ़ 10, 1933

No. 1251]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2011/ASADHA 10, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2011

का.आ.1499(अ).—अधिसूचना के निम्नलिखित प्रारूप को जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (v) और खण्ड (xiv) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, जिसे पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित किया जाता है;

ऐसे व्यक्ति जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध हैं, वे ऐसा लिखित रूप में, इस अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के विचार करने के लिए सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 या इलेक्ट्रॉनिकली Bhagirathi.Notification@Gmail.com. पर भेज सकेंगे।

उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति से उपर्युक्त यथाविनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप अधिसूचना

भागीरथी नदी जो गंगा नदी की एक प्रमुख सहयोगी नदी है, 3892 मीटर ऊंचाई से गौमुख से उद्गमित होती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने से पूर्व तीव्र ढाल में लगभग 215 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। नदी इस दूरी में अधिकतर गहरे और संकरे महाखड्ड में बहती है;

और नदी पर कई जल विद्युत परियोजनाएं चालू की गई हैं या प्रस्तावित हैं या क्रियान्वयन के अधीन हैं, अतः यह संभावना है कि जिनका नदी की पारिस्थितिकी, बहाव और प्रकृति पर प्रभाव पड़ेगा।

और यह वांछनीय है कि नदी के पर्यावरणीय बहाव और पारिस्थितिकी का अनुरक्षण करने के लिए गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी नदी के 135 किलोमीटर के खण्ड और नदी के दोनों किनारों से 100 मीटर दूरी तक का क्षेत्र पारिस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भागीरथी नदी के गौमुख से उत्तरकाशी तक के खंड को पारिस्थितिक संवेदनशील परिक्षेत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदनशील परिक्षेत्र कहा गया है) घोषित करती है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदनशील परिक्षेत्र की सीमाएं-** उक्त पारिस्थितिक संवेदनशील परिक्षेत्र गौमुख से उत्तरकाशी तक के खंड और नदी के दोनों किनारों से एक सौ मीटर दूरी तक का 135 किलोमीटर के अंतर्गत का क्षेत्र है ।

2. **पारिस्थितिक संवेदनशील परिक्षेत्र के लिए आंचलिक महायोजना-**

(1) पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और उसे भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य के सभी संबंधित विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, विद्युत, नगरपालिका, राजस्व, लोक निर्माण विभाग और उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सम्यक् भागीदारी से इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को सम्मिलित करने हेतु तैयार किया जाएगा ।

(3) आंचलिक महायोजना निरावृत्त क्षेत्रों को पुनःस्थापन करने, विद्यमान जलीय निकायों के संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल संभरणों के प्रबंधन, भूमिगत जल प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताएँ तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलू जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, का उपबंध करेगा ।

(4) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान ग्राम व्यवस्थापन, वनों के प्रकारों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उर्वर भूमि, हरित क्षेत्रों, बागान क्षेत्रों, फलोद्यानों, झीलों तथा क्षेत्र में स्थित अन्य जल निकायों को चिन्हित करेगा ।

(5) आंचलिक महायोजना जल विद्युत परियोजनाओं समेत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए किए जाने वाले विनिश्चयों के लिए राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए संदर्भ दस्तावेज होगा ।

3. **पारिस्थितिक संवेदनशील परिक्षेत्र में प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप-**पारिस्थितिक संवेदनशील परिक्षेत्र में निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध होंगे, अर्थात् :-

- (क) 25 मेगावॉट से अधिक क्षमता के नए जल विद्युत संयंत्र स्थापित करना ;
- (ख) किन्हीं नए औद्योगिक प्रयोजनों के लिए नदी के जल का निष्कर्षण ;
- (ग) स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए सभी प्रकार के खनन (गौण और प्रमुख खनिज) ;
- (घ) पत्थर का खनन और तोड़ना
- (ङ) वन काटना और काष्ठ आधारित नए उद्योग स्थापित करना ;

- (घ) कोई नए प्रदूषणकारी और अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग ;
- (छ) अनुपचारित मल जल और औद्योगिक बहिस्राव छोड़ना ;
- (ज) किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट का निपटान और ठोस अपशिष्ट को जलाना या भट्ठी में जलाना ।

4. **पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में निर्बंधित क्रियाकलाप-** पारिस्थितिक संवेदनशील परिक्षेत्र में निम्नलिखित क्रियाकलाप निर्बंधित होंगे अर्थात् :--

(क) **जल-**(i) भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल भूमि के अधिभोगी के संभावपूर्ण कृषि और घरेलू उपभोग के लिए ही अनुज्ञात किया जाएगा तथा राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाए भूमिगत जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ; (ii) कृषि समेत जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे ।

(ख) **ध्वनि प्रदूषण-**पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग, उत्तराखंड पारिस्थितिकी संवेदनशील परिक्षेत्र में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने के लिए प्राधिकारी होगा ।

(ग) **बहिस्रावों का निर्गमन** -उपचारित बहिस्राव जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(घ) **जल विद्युत प्लांट-**लघु जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावॉट से कम) के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित होगी ।

(ङ) **ठोस अपशिष्ट-**(i) पारिस्थितिक संवेदनशील परिक्षेत्र से बाहर ठोस अपशिष्ट का निपटान केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना संख्यांक का.आ.908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा जारी किए गए नगरीय निकाय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) स्थानीय प्राधिकारी ठोस अपशिष्ट के जैव अपघटनीय और गैर जैव अपघटनीय अवयवों में पृथक्करण के लिए योजना बनाएंगे ।

(iii) जैव अपघटनीय सामग्री का अधिमानतः कंपोस्ट या कृमिसंवर्धन द्वारा पुनर्चक्रण किया जा सकेगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र से बाहर चिन्हित स्थल पर पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य रीति में निपटान की जा सकेगी ;

(च) **पर्वतीय ढालों पर विकास और उनका संरक्षण :**

(i) आंचलिक महायोजना पर्वतीय ढालों पर उन क्षेत्रों को इंगित करेगा जहां विकास अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(ii) उन क्षेत्रों में कोई विकास नहीं किया जाएगा जिनमें तीव्र ढाल है या ऐसे क्षेत्र जो त्रुटिपूर्ण या परिसंकटमय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं अथवा ऐसे क्षेत्र जो झरना मार्ग या पहले दर्जे के

प्रवाहों पर हैं या अत्यधिक मात्रा में क्षरण वाले ढालों पर हैं जैसा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर चिन्हित किया जाए ;

(iii) विद्यमान तीव्र पर्वतीय ढालों या किसी अत्यधिक मात्रा में क्षरण वाले ढालों पर कोई विकास अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(छ) प्राकृतिक झरने-सभी झरनों के जल ग्रहण क्षेत्र चिन्हित किए जाएंगे और उनके संरक्षण के लिए तथा उन झरनों के प्राकृतिक स्थिति में नवीकरण के लिए जो सूख गए हैं, योजनाएं आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी और इन क्षेत्रों पर या इनके निकट विकास गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कड़े दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे ;

(ज) पर्वतीय मार्ग-पर्वतीय मार्गों के सनिर्माण और अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश विरचित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किए जाएंगे ; अर्थात् :--

- (i) 5 कि.मी. लंबाई से अधिक के पारिस्थितिक संवेदनशील परिक्षेत्र में डामर रहित समेत किसी मार्ग के संनिर्माण के लिए (विद्यमान मार्गों के विस्तार या चौड़ीकरण समेत) ;
- (ii) मार्ग काटने तिर्यक निकास संकर्म और पुलिया के परिणाम स्वरूप हुई पर्वतीय ढाल अस्थिरताओं के उपचार के लिए मार्ग के डिजाइन में जैव इंजिनियरिंग और अन्य उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग कर किया जाएगा और प्रस्तावित मार्ग के लागत प्राक्कलन में ऐसे उपायों की लागत सम्मिलित करने के उपबंध किए जाएंगे ;
- (iii) मलबे को खड्ड या ढालों के नीचे निपटान नहीं किया जाएगा बल्कि मार्गों के संनिर्माण में उपयोग किया जाएगा तथा उपयुक्त और चिन्हित अविस्थानों पर उचित रीति में अप्रयुक्त मलबे के निपटान के लिए भी उपबंध किए जाएंगे जिससे उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर प्रभाव न पड़े तथा मलबे का उपचार और भूदृश्य निर्माण जैव इंजीनियरिंग और अन्य उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग करके किया जाएगा और प्रस्तावित मार्ग के लागत प्राक्कलन में ऐसे उपायों की लागत सम्मिलित करने के उपबंध किए जाएंगे ;
- (iv) सभी मार्गों में पर्याप्त संख्या में मार्ग के किनारे निकास नालियों का उपबंध किया जाएगा और इन नालियों को निपटान को बहाने के लिए रुकावट से मुक्त रखा जाएगा तथा मार्ग के किनारे की नालियां क्षेत्र की प्राकृतिक निकास प्रणाली से संयोजित होंगी ;
- (v) वानस्पतिक आच्छदन की हानि को न्यूनतम करने के लिए संरक्षण का चयन किया जाएगा ;
- (vi) कटान और भरण के वृहद संतुलन तथा अनावश्यक कटान से बचने समेत मार्गों को डिजाइन करते समय उचित डिजाइन मानकों का अनुसरण किया जाएगा ।

4. मानीटरी समिति-

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है ।

(2) मानीटरी समिति (क) दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, (ख) मानीटरी समिति का अध्यक्ष सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय विवादकों की समझ वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

- (i) भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ;
- (ii) भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला पर्यावरण (विरासत संरक्षण समेत) के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि ;
- (iii) सदस्य सचिव, उत्तराखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड ;
- (iv) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार ;
- (v) मुख्य वन संरक्षक ;
- (vi) उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का प्रतिनिधि ;
- (vii) राज्य सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि ;
- (viii) अंचल में विख्यात शैक्षणिक संस्था का प्रतिनिधि ;
- (ix) जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी-सदस्य सचिव ।

(3) वे क्रियाकलाप जिनमें पूर्व अनुज्ञा या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो समय-समय पर यथासंशोधित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, तारीख 14 सितंबर, 2006 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(4) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके विचार विमर्श में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकेगी ।

(5) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य सचिव, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(6) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा ।

(7) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे ।

[फा. सं. 25/3/2010-आरई]

डॉ. जी. वी. सुब्रह्मन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2011

S.O. 1499(E).— The following draft of a notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within a period of Sixty days from the date of publication of the notification in the Gazette of India through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: Bhagirathi.Notification@Gmail.com

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft notification before the expiry of the period as specified above will be taken into consideration of the Central Government.

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, the River Bhagirathi, a major tributary of river Ganga, originates from Gaumukh at an elevation of 3892 meter flows for a stretch of about 215 kilometer in a steep slope before it joins Alaknanda at Dev Prayag. River travels through a deep and narrow gorge in the majority of its stretch;

AND WHEREAS, a number of hydro power projects have been commissioned or proposed or under implementation on the river, it is likely that there will be an impact on the ecology, flow and character of the river.

AND WHEREAS, it is desirable that for the maintenance of environmental flow and ecology of the river, area covering the 135 kilometer stretch of the river Bhagirathi from Gaumukh to Uttarkashi and upto one hundred meter distance from both the banks of the river shall be declared as an Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the

Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the stretch of the river Bhagirathi from Gaumukh to Uttarkashi as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone), namely:-

1. Boundaries of Eco-sensitive Zone.- The said Eco-sensitive Zone is the area covering 135 km stretch from Gaumukh to Uttarkashi and upto one hundred meter from both the banks of the river.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone -

- (1) For the purpose of the Eco-sensitive Zone the State Government shall prepare a Zonal Master Plan within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and the same shall be approved by the Ministry of Environment and Forests, Government of India.
- (2) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments of Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Power, Municipal, Revenue, Public Works Department and Uttarakhand State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it.
- (3) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (4) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies along the stretch.
- (5) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them for various developmental projects including hydroelectric power projects.

3. Prohibited activities in the Eco-sensitive Zone.- In the Eco-sensitive Zone, the following activities shall be prohibited, namely:-

- (a) setting up of new Hydro-electric Power Plants with a capacity of more than 25MW;
- (b) abstraction of river water for any new industrial purposes;
- (c) all types of mining (minor and major minerals) except for the domestic needs of local residents;
- (d) stone quarrying and crushing;
- (e) deforestation and setting up of any wood based industry;
- (f) any new polluting and highly polluting industries;

- (g) discharge of untreated sewage and industrial effluents;
- (h) disposal of any kind of solid waste and burning or incinerating solid waste;

4. Restricted activities in the Eco-sensitive Zone.- In the Eco-sensitive Zone, the following activities shall be restricted, namely:-

(a) Water.- (i) the extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption of the occupier of the plot and the sale of ground water shall not be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board; (ii) all steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture;

(b) Noise pollution.- the Environment Department or the State Forest Department, Uttarakhand shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone;

(c) Discharge of effluents.- the treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;

(d) Hydro-electric power plants.- small hydro-electric power projects (less than 25MW) shall require prior permission from the Ministry of Environment and Forests;

(e) Solid Wastes.- (i) the solid waste disposal outside Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 issued by the central Government vide notification number - S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 and amended from time to time.

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(f) Development on and protection of hill slopes:

(i) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where development shall not be permitted;

(ii) no development shall be undertaken in areas having a steep slope or areas which fall in fault or hazard zones or areas falling on the spring lines and first order streams or slopes with a high degree of erosion as identified by the State Government on the basis of available scientific evidence;

(iii) no development on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(g) Natural Springs.- the catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the strict guidelines shall be drawn up by the State Government to ban development activities at or near these areas;

(h) Hill Roads.- the following guidelines shall be framed for the construction and maintenance of hill roads and incorporated in the Zonal Master Plan; namely:-

- (i) for construction of any road including untarred in the Eco-sensitive Zone of more than 5 km length (including the extension or widening of existing roads);
- (ii) provision shall be made in the design of the road for treatment of hill slope instabilities resulting from road cutting cross drainage works and culverts using bio-engineering and other appropriate techniques and by including the cost of such measures in the cost estimate of the proposed road;
- (iii) the debris shall not be dumped down the khud or slopes but shall be subsumed in the construction of roads and the provision shall also be made for disposal of unused debris in appropriate manner at suitable and identified locations so as not to affect the ecology of the area adversely and the debris shall be treated and landscaped using bio-engineering and other appropriate techniques and the cost of such measures shall be included in the cost estimate of the proposed road;
- (iv) all roads shall be provided with adequate number of road side drains and these drains shall be kept free from blockage for runoff disposals and this run off from the road side drainage shall be connected with the natural drainage system in the area;
- (v) alignment shall be selected so as to minimise loss of vegetal cover;
- (vi) appropriate design standards shall be followed while designing the roads including mass balancing of cut and fill and avoidance of unnecessary cutting.

4. Monitoring Committee.-

(1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consist of (a) not more than ten members. (b) the Chairperson of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

- (i) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India;

- (ii) one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India;
- (iii) Member Secretary, Uttarakhand State Pollution Control Board;
- (iv) senior Town Planner of the area;
- (v) the Chief Conservator of Forests;
- (vi) the representative of Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited;
- (vii) the representative of State Irrigation Department;
- (viii) the representative of renowned educational institution in the region;
- (ix) the District Magistrate, Uttarkashi – Member Secretary.

(3) The activities requiring prior permission or environmental clearance shall be referred to the Ministry of Environment and Forests, which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2006 as amended from time to time.

(4) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(5) For non-compliance of the provisions of this notification, the Chairperson or Member Secretary of Monitoring Committee shall be the competent authority to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.

(6) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken report by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests and the Ministry shall give its directions from time to time for effective discharge of the functions by the Monitoring Committee.

(7) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

[F. No.25/3/2010-RE]

Dr. G.V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'